lected or delinquent children and for the trial of delinquent children in the Union territories. Similar Acts have also been enacted by most of the States. There is, however, no proposal at present to introduce legislation throughout the country for combating juvenile delinquency.

U.P. Bihar Border Dispute

*1140. **Shri Shree Narayan Das:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Shri C. M. Trivedi appointed to go into the border dispute between the States of Bihar and Uttar Pradesh has submitted his report; and

(b) if so, the important features of his report?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) Not, yet.

(b) Does not arise.

सस्ती ब्रिटिश पाठ्य पुस्तकें

*११४३. **श्रीमती जोहराबेन चावड़ा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय तथा एक ब्रिटिश पुस्तक प्रकाशन संस्थान के बीच सस्ती पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करने के बारे में कोई करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की पुस्तकों का प्रकाशन होना है तथा इनका किन वर्गों के लोगों के लाभार्थ प्रकाशन होगा; और

(ग) इस परियोजना के अधीन मंत्रालय का कितना धन व्यय करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री सु० क० चागला) : (क) सिद्धान्तरूप में करार हो चुका है ।

(ख) मुख्य रूप से ये पाठ्य पुस्तकें होंगी जिनका प्रकाशन विद्यार्थियों के लाभ के लिए होगा ।

(ग) भारत सरकार की इस सम्बन्ध में कोई वित्तीय जिम्मेदारी नहीं होगी ।

पाकिस्तानी रेडियो का प्रसारण

*११४६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान तनाव पैदा करने की दृष्टि से भारत में हुए साम्प्रदायिक उपद्रवों आदि की सामान्य घटनाओं को अतिरंजित करके रेडियो पर प्रसारित करता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत में पाक रेडियो सुनने सुनाने पर कोई पाबन्दी नहीं है और देश में बहुत सी जगहों पर जान-बूझ कर सार्वजनिक रूप से प्रसारण सुनवाया जाता है; और

(ग) क्या सरकार उस पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) पाकिस्तान रेडियो द्वारा प्रसारण के ऐसे कुछ मामले हमारे नोटिस में आये हैं ।

(ख) क्योंकि इस सम्बन्ध में भारत में कोई प्रतिबन्ध नहीं है, ऐसे प्रसारण सार्वजनिक रूप में सुने जा सकते हैं, अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता कि ऐसा जान-बूझ कर किया जाता है ।

(ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।